गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)
GAIL (India) Limited
(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,
16 भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110066, इंडिया
GAIL BHAWAN,
16 BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110066, INDIA
फोन/PHONE : +91 11 26182955
फैक्स/FAX : +91 11 26185941
ई–मेल/E-mail : info@gail.co.in

एनडी/गेल/सेक्ट/2021

18.08.2021

1. लिस्टिंग अनुपालन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट सं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई-400 051 **स्क्रिप कोड: गेल-ईक्यू**	2. लिस्टिंग अनुपालन बीएसई लिमिटेड फ्लोर 1, फिरोज़ जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400001 **स्क्रिप कोड: 532155**

विषय : 37वीं एजीएम की सूचना भिजवाने का समाचार पत्र प्रकाशन के संबंध में

प्रिय महोदय/ महोदया,

यह सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियम 47 के अनुपालन में है ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कृपया अनुलग्नक प्राप्त करें।

उपर्युक्त आपकी जानकारी एवं रिकॉर्ड हेतु है।

धन्यवाद,
भवदीय,

(ए के झा)
कंपनी सचिव

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

अफगानिस्तान से भारतीय स्वदेश लौटे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगान स्थिति पर मंगलवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की

एजेंसियां

अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान के नियंत्रण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इससे पहले, काबुल में भारतीय राजदूत एवं दूतावास के कर्मियों समेत 120 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का एक विमान मंगलवार को अफगानिस्तान से भारत पहुंच गया।

सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक के बारे में सूत्रों ने कहा कि इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला, अफगानिस्तान में भारत के राजदूत आर टंडन सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

इस बीच, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत सभी भारतीयों की अफगानिस्तान से सकुशल वापसी को लेकर प्रतिबद्ध है और काबुल हवाईअड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों की बहाली होते ही वहां फंसे अन्य भारतीयों को स्वदेश लाने का प्रबंध किया जाएगा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद सुरक्षा हालात के मद्देनजर भारतीय दूतावास के कर्मियों को लेकर एक सैन्य विमान स्वदेश लौट आया। भारतीय वायुसेना का सी-17 विमान राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के पास स्थित हिंडन वायु सेना स्टेशन आने के क्रम में पूर्वाह्न करीब सवा ग्यारह बजे गुजरात के जामनगर स्थित वायुसेना स्टेशन पर उतरा था। ऐसी खबरें हैं कि इस विमान से कुछ अन्य भारतीय नागरिक भी लौटे हैं। अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुद्रेंद्र टंडन ने जामनगर में पत्रकारों से कहा कि काबुल में हालात बेहद खराब हैं और वहां फंसे भारतीयों को वाणिज्यिक उड़ान सेवा शुरू होने के बाद वापस लाया जाएगा। टंडन ने कहा कि दूतावास में हमारे 192 कर्मी हैं जिन्हें दो चरणों में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तीन दिन के भीतर अफगानिस्तान से वापस लाया गया है। पिछले साल अगस्त में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में दायित्व संभालने वाले टंडन ने कहा कि काबुल में तेजी से बदली स्थिति के बीच दूतावास ने अनेक परेशान भारतीयों की मदद की और उन्हें शरण भी दी।

इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की है। जयशंकर अमेरिका के चार दिवसीय दौरे पर न्यूयॉर्क में हैं। उन्होंने सोमवार देर रात तीन बजे ट्वीट में कहा कि उन्होंने ब्लिंकन के साथ अफगानिस्तान के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने काबुल में हवाईअड्डा संचालन बहाल करने की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया। जयशंकर ने कहा कि वह इस संबंध में अमेरिकी प्रयासों की बहुत सराहना करते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि जयशंकर और ब्लिंकन ने अफगानिस्तान संबंधी हालात पर चर्चा की। भारत अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष है। इसी के मद्देनजर जयशंकर सुरक्षा परिषद के इस सप्ताह दो उच्च स्तरीय अहम कार्यक्रमों की अध्यक्षता के लिए सोमवार को न्यूयॉर्क आए।

इस बीच, भारत ने मंगलवार को अफगान नागरिकों के लिए आपात ई-वीजा जारी करने की घोषणा की। सभी अफगान नागरिक (चाहे वे किसी भी धर्म में आस्था क्यों नहीं रखते हों) ऑनलाइन इस वीजा के आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों पर नई दिल्ली में विचार होगा। भारत ने यह ई-वीजा उन लोगों के लिए जारी किया है जो तालिबान के कब्जे के बाद भारत आना चाहते हैं।

जामनगर स्थित वायुसेना के अड्डे पर अफगानिस्तान से वापस लौटे भारतीयों का स्वागत करते अधिकारी फोटो-पीटीआई

काबुल में सरकार गठन पर चर्चा तेज

अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां सरकार गठन पर चर्चा तेज हो गई है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि भविष्य में वहां तालिबान के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में गैर-तालिबान सदस्य भी शामिल किए जा सकते हैं। इस विषय पर राजधानी काबुल में चर्चा हो रही है। इस बातचीत से जुड़े लोगों ने मंगलवार को नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि कहा कि अगले एक या दो दिन में इस संबंध में कोई ठोस नतीजा निकल सकता है।

वरिष्ठ तालिबान नेता आमिर खान मुत्तकी पहले ही अब्दुल्ला अब्दुल्ला और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत काबुल के राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई दौर की वार्ता कर चुके हैं। अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने एक बार देश के वार्ता परिषद की अगुवाई की थी। कम से कम एक दौर की वार्ता रात भर चली। तालिबान के शासन के दौरान शिक्षा मंत्री रहे मुत्तकी ने पिछले सप्ताह के आखिर में राष्ट्रपति अशरफ गनी के राष्ट्रपति भवन से चले जाने से पहले से ही अफगान राजनीतिक नेताओं के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया था। मुत्तकी ने काबुल के तालिबान के कब्जे में आने से पहले अमेरिका समर्थित धड़ों से संपर्क करने का प्रयास किया। यह सरकार में सभी लोगों को शामिल करने की तालिबान की शुरुआती पहल जान पड़ती है। तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने पहले कहा था कि यह एक समावेशी अफगान सरकार होगी।

आम माफी की घोषणा

इस बीच, तालिबान ने मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा की और महिलाओं से उसकी सरकार में शामिल होने का आह्वान किया। तालिबान के प्रतिनिधियों ने लोगों के मन में व्याप्त भय भी दूर करने की कोशिश की। तालिबान के डर से सोमवार को काबुल छोड़कर भागने की कोशिश करते लोगों की वह से स्थानीय हवाईअड्डे पर अफरा-तफरी मच गई थी। इस घटना में कई लोग मारे गए थे। काबुल में उत्पीड़न या लड़ाई की बड़ी घटना की खबर अब तक नहीं आई है। तालिबान द्वारा जेलों पर कब्जा कर कैदियों को छुड़ाने एवं हथियारों को लूटने की घटना के बाद कई शहरी घरों में मौजूद हैं, लेकिन भयभीत हैं। कई महिलाओं ने आशंका जताई है कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के दौरान महिलाओं को और अधिकार देने का पश्चिमी प्रयोग तालिबान के शासन में कायम नहीं रहेगा।

तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य इनामुल्ला समानगनी ने आम माफी का वादा किया है। यह पहली बार है जब तालिबान की ओर से संघीय स्तर पर शासन को लेकर टिप्पणी की गई है। समानगनी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि आम माफी से उसका क्या अभिप्राय है। हालांकि, अन्य तालिबानी नेताओं ने कहा कि वे उन लोगों से बदला नहीं लेना चाहते हैं जो पूर्ववर्ती सरकार या विदेशों में कार्यरत थे। इस बीच, मंगलवार को नाटो के अफगानिस्तान में वरिष्ठ असैन्य प्रतिनिधि स्टीफेनो पोंटेकार्वो ने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दिख रहा है कि हवाईअड्डे की उड़ान पट्टी खाली है और अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तस्वीर में चेन से बनी सुरक्षा दीवार के पीछे सेना के मालवाहक विमान देखे जा सकते हैं।

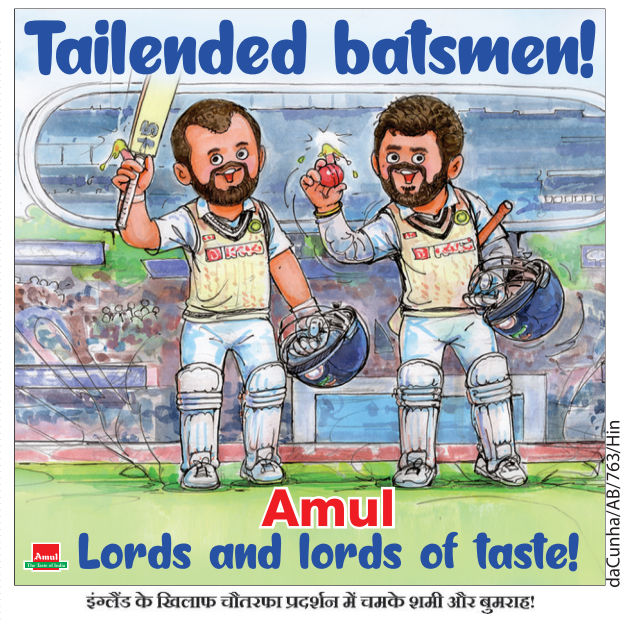

daCunha/AB/763/Hin

इंग्लैंड के खिलाफ चौतरफा प्रदर्शन में चमके शमी और बुमराह!

पेगासस विवाद

न्यायालय का केंद्र सरकार को नोटिस

सर्वोच्च न्यायालय ने कथित पेगासस जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यह स्पष्ट किया कि वह नहीं चाहता कि सरकार ऐसी किसी बात का खुलासा करे जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता हो। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस के पीठ ने यह टिप्पणी सरकार के यह कहने के बाद की कि हलफनामे में सूचना की जानकारी देने से राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जुड़ा है।

पीठ ने कहा कि उसने सोचा था कि सरकार एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी लेकिन इस मामले में सिर्फ सीमित हलफनामा दाखिल किया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह 10 दिन बाद इस मामले को सुनेगी और देखेगी कि इसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। केंद्र का पक्ष रख रहे सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने सोमवार को दाखिल हलफनामे में अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया था। मेहता ने पीठ को बताया, 'हमारी सुविचारित प्रतिक्रिया वही है जो हमने सम्मानपूर्वक अपने पिछले हलफनामे में दी थी। कृपया इस मामले को हमारे नजरिये से देखें क्योंकि हमारा हलफनामा पर्याप्त है। भारत सरकार देश की सर्वोच्च अदालत के सामने है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि वह वह सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करेगी और यह समिति शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, 'छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है' और इस मामले से राष्ट्रीय सुरक्षा का पहलू जुड़ा है। मेहता ने कहा कि यह मामला 'सार्वजनिक बहस का मुद्दा' नहीं हो सकता और विशेषज्ञों की समिति शीर्ष अदालत को रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा, 'यह एक संवेदनशील मामला है जिसे संवेदनशीलता से निपटा जाना चाहिए।' भाषा

टीके की सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड

भारत ने 24 घंटे में कोविड-19 टीके की 88.13 लाख से अधिक खुराक दी है जो एक दिन में सबसे अधिक खुराक लगाने का रिकॉर्ड है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया, 'भारत ने एक दिन में सबसे अधिक कोविड-19 टीके की खुराक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। कल (बीता हुआ) इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े टीका अभियान के तौर पर दर्ज होगा। बधाई।' मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार की सुबह तक मिली अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 62,12,108 टीकाकरण सत्र में अबतक कोविड-19 टीके की 55,47,30,609 खुराक दी गई है। अबतक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से कोविड-19 टीके की 56.81 करोड़ खुराक मुहैया कराई गई है और 1,09,32,960 खुराकों की आपूर्ति प्रक्रियागत है। मंत्रालय के मुताबिक इस वक्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास 2.25 करोड़ टीके की खुराक मौजूद है। भाषा

टीके के पेच से दोबारा बंद हुए मॉल

सुशील मिश्र

कोरोना के मामलों में कमी आने और व्यापारी संगठनों की लगातार मांग को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 15 अगस्त से दुकानों और रेस्टोरेंटों की समय सीमा बढ़ा दी। साथ ही 130 दिनों के इंतजार के बाद शॉपिंग मॉल भी खुल गए लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नए दिशानिर्देश के मुताबिक मॉल में वही कर्मचारी जा सकते हैं जिन्होंने कोरोना टीके की दोनों खुराक ली हैं। इस शर्त को अधिकांश शॉपिंग मॉल पूरा नहीं कर पा रहे हैं जिसके चलते मंगलवार को लगभग सभी मॉल दोबारा बंद हो गए।

शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इनफिनिटी मॉल के सीईओ मुकेश कुमार के मुताबिक चार महीने से कारोबार बंद रहने के बाद कुछ

उम्मीद जगी थी लेकिन सरकार द्वारा ऐसी शर्तें लगाई गईं जिन पर व्यावहारिक तौर पर खरा उतरना मुमकिन नहीं है, सभी मॉल दो दिन खुलने के बाद एक बार फिर बंद हो गए हैं। कर्मचारियों के लिए दोनों खुराक जरूरी वाला परिपत्र सोमवार शाम को जारी किया गया। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि सभी मॉल हर रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराक का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। चूंकि 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश बिंदुओं पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने की जरूरत है।

इस बीच प्रशासन के एक निर्णय ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी। प्रशासन ने माल डिब्बों में सामान के परिवहन की अनुमति दे दी है। इससे टेम्पो के मंहगे भाड़े से छुटकारा मिलेगा। रेलवे लोकल में सफर में और भी छूट देने के संकेत देने लगा है। कोरोना टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को 15 अगस्त से लोकल में सफर की अनुमति दी मिल गई है। लोकल में भीड़ नियंत्रित रहती है तो जल्द ही एक खुराक ले चुके लोगों को भी लोकल में सफर की अनुमति मिल सकती है।

गेल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

गेल (इंडिया) लिमिटेड के शेयरधारकों हेतु सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन में कंपनी के सदस्यों की 37वीं (सैंतीसवीं) वार्षिक आम सभा (एजीएम) **गुरुवार, दिनांक 09 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी। इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (प्रासंगिक प्रावधानों) को एमसीआई के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं.17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 **(एमसीए परिपत्र)** तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **('सेबी')** के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/पी/सीआईआर/2021/602 दिनांक 23 जुलाई, 2021 **("सेबी परिपत्र")** के साथ पढ़ा जाए जिनमें वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा के आयोजन की प्रक्रियाओं और तरीकों के बारे में बताया गया है।

उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार 37वीं एजीएम की सूचना और वित्त वर्ष 2020-21 हेतु कंपनी की एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दी गई है जिनकी ई-मेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डी. पी.) अथवा आर. एंड टी. ए. के पास पंजीकृत हैं। उन्हें कंपनी की वेबसाइट (www.gailonline.com), स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट (www.evotingindia.com) पर भी होस्ट किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) के विनियम 44 तथा कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) का उपयोग करके 37वीं वार्षिक आम सभा की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर मतदान के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा सहर्ष प्रदान कर रही है। रिमोट-ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी द्वारा डिपाजिटरी सर्विसेज अर्थात सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड को तैनात किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **रविवार, दिनांक 05 सितंबर, 2021 (प्रातः 9:00 बजे) (आईएसटी) से प्रारंभ होगी और बुधवार, दिनांक 08 सितंबर, 2021 (सायं 5:00 बजे) (आईएसटी)** को समाप्त होगी। उसके पश्चात रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के उपरांत उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

वे व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में सदस्य के रूप में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी स्वामियों के रजिस्टर में निर्दिष्ट तिथि अर्थात **गुरुवार, दिनांक 02 सितंबर, 2021** को पंजीकृत है, केवल वही रिमोट ई-मतदान की सुविधा का लाभ लेने अथवा एजीएम में भाग लेने या एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होगा।

रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोटिंग करने वाले सदस्य वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग ले सकते हैं लेकिन वे पुनः मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे। किसी संकल्प पर ई-वोटिंग द्वारा एक बार मतदान करने के पश्चात सदस्य को उसे परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा https://www.evotingindia.com लिंक पर उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाल सके और अन्यथा ऐसा करना जिन्हें वंचित नहीं हैं, केवल वही एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने के लिए पात्र होंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम सभा के नोटिस के रिमोट ई-वोटिंग भाग के अनुदेशों पर ध्यान दें। यदि आपके पास ई-वोटिंग सिस्टम से एजीएम एवं ई-वोटिंग में भाग लेने से संबंधित कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन पर उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल लिख सकते हैं helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा 022-23058738 और 022-23058542/43 पर संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप में हमारे आर. एंड टी. ए. से admin@mcsregistrars.com या श्री अजय दलाल, महाप्रबंधक, एमसीएस एसटीए से फोन नं. 91-11-41406149-52 {पताः एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, **यूनिटः गेल (इंडिया) लिमिटेड,** प्रथम तल, एफ-65, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेस-I, नई दिल्ली -110020} से संपर्क करें।

यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग हेतु सीडीएसएल/एनएसडीएल में पहले से ही पंजीकृत है तो विद्यमान लॉग इन आई-डी और पासवर्ड ई-वोटिंग हेतु प्रयुक्त होगा। जो व्यक्ति कंपनी द्वारा नोटिस जारी होने के पश्चात शेयर अधिगृहीत किए हैं और कंपनी के सदस्य बने हैं तथा कट ऑफ तारीख को शेयर धारण करते हैं, वे लॉग इन आईडी तथा पासवर्ड हासिल करने के लिए shareholders@gail.co.in अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने शेयरधारिता के विवरण सहित अनुरोध भेज सकते हैं।

अपने सदस्यों की बेहतर सेवा हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए अनुरोध है कि जो सदस्य नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH) सुविधा का लाभ लेने के लिए इच्छुक हैं अर्थात बैंक खाते में लाभांश राशि का प्रत्यक्ष क्रेडिट प्राप्त करने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी (DP) (यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाता है) या आर एंड टी ए/कंपनी (यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा जाता है) के साथ बैंक विवरण अपडेट करें।

इसके अतिरिक्त भौतिक रूप में शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक शेयरधारिता को डिमैटेरियलाइज करें। सेबी परिपत्र सं.सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/आरटीएएमबी/सीआईआर/पी/2020/236 दिनांक 2 दिसम्बर, 2020 को ध्यान में रखते हुए कंपनी/आरएंडटीए द्वारा भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण के लिए अनुरोध (प्रतिभूतियों के स्थानांतरण या संचरण के मामले को छोड़कर) पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सदस्य (यों) जिन्होंने अभी तक अपने डिविडेंड वारंट(टों) को भुनाया नहीं है वेIEPF को ट्रांसफर करने की नियत तारीख से कम से कम 3 सप्ताह पहले डिमांड ड्राफ्ट (टों) जारी करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए आरएंडटीए/कंपनी से संपर्क कर सकते हैं। सदस्य (यों) विस्तृत संदर्भ के लिए कंपनी की वेबसाइट पर **'निवेशक जोन'** अनुभाग पर जा सकते हैं। सदस्य (ओं) को अपने अनुरोध/शिकायत दर्ज करने की सुविधा के लिए, यदि कोई है, तो आरएंडटीए और कंपनी की निर्दिष्ट ई-मेल आईडी admin@mcsregistrars.com या shareholders@gail.co.in पद है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के संदर्भ में कंपनी 09 सितम्बर, 2021 को पूर्वाह्न 11.30 बजे से एजीएम के समापन तक वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का एकतरफा लाइव वेबकास्ट प्रदान कर रही है। उक्त को आप गेल की वेबसाइट (www.gail.online.com) पर एक्सेस कर सकते हैं।

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.08.2021
ई-मेलः shareholders@gail.co.in
फोनः 011-26182955
फैक्सः 011-26185941
सीआईएनः L40200DL1984GOI018976

कृते गेल (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
(ए के झा)
कंपनी सचिव

www.gailonline.com | पंजी.: कार्या.: 16, भीकाएजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066. Follow us on

स्वास्थ्य क्षेत्र में उतरेंगे विनोद के दासरी

शाइन जैकब

रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्याधिकारी के रूप में दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद विनोद के दासरी ने सस्ती स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास के अपने शौक पर काम करने के लिए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हालांकि इस बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा चर्चा नहीं हुई है कि उनका भविष्य का शौक क्या है? केवल मीडिया को बताया गया था कि यह 'गैर-लाभकारी' उद्यम होगा। दासरी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'यह अभी शुरुआती दौर में है। मैं बहुत से वर्षों तक कारोबारी अगुआ रहने के बाद समाज को कुछ लौटाना चाहता हूं। मेरी योजना अपनी पत्नी सरिता द्वारा स्थापित स्वास्थ्य उद्यम पर आगे बढ़ने की है, जो खुद एक डॉक्टर हैं।' वह रॉयल एनफील्ड से जुड़ने से पहले एक अन्य प्रमुख वाहन विनिर्माता कंपनी अशोक लीलैंड में वर्ष 2011 से प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी थे।

दासरी ने 4 अगस्त को चेन्नई के नुंगमबक्कम में उनके परिवार के स्वामित्व वाले 40 बेड के मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल विजय गंगा स्पेशियलिटी केयर लिमिटेड (वीजीएससी) का उद्घाटन किया था। दासरी ने कहा कि यह अस्पताल अगले 15 दिन के भीतर चालू हो जाएगा।

उन्होंने कहा, 'इसकी सफलता के आधार पर हम आगे और अस्पताल खोलने का फैसला लेंगे। हमने इस अस्पताल पर करीब 75 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हमने इस नए उद्यम पर जितना निवेश किया है, वह कंपनी जगत में एक मामूली राशि हो सकती है।' वीएससीजी की स्थापना डॉ. सरिता ने वर्ष 2009 में की थी और इसे वर्ष 2013 में मायलापुर में एक छोटे क्लिनिक के रूप में शुरू किया गया था। नया अस्पताल व्यापक सेवाएं मुहैया कराएगा, जिनमें रोकथाम एवं स्वास्थ्य, वेस्क्यूलर सेवाएं, नेफ्रोलॉजी सेवाएं, यूरोलॉजी सेवाएं, सामान्य स्पेशियलिटी, अस्पताल देखभाल, जांच और उपचार सेवाएं शामिल हैं।

उन्होंने कहा, 'भारत में हर पांच में से एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। हर तीन में से एक को उच्च-रक्तचाप की समस्या है और मेरी पत्नी इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। ऐसे में हमने सोचा है कि हम कुछ मिलकर बनाने के लिए कैसे उनके और मेरे कौशल का लाभ ले सकते हैं।' डॉ. सरिता हुबली स्थित कर्नाटक मेडिकल कॉलेज से स्नातक हैं और उन्होंने अमेरिका के ओहायो के आल्टमैन हॉस्पिटल से इंटरनल मेडिसन में विशेषज्ञता और क्लीवलैंड क्लिनिक फाउंडेशन (सीसीएफ) से नेफ्रोलॉजी में अति विशेषज्ञता हासिल की है।

यह दंपती वीजीएससी की डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट प्रशिक्षण अकादमी का भी विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिसे ट्रेन4लाइफ के नाम से भी जाता है

विनोद के दासरी

ताकि छात्रों, नर्सिंग अटेंडेंट और मौजूदा डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्टों के कौशल को विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा, 'लोगों को प्रशिक्षण और उनका करियर बनाने में मदद क्यों नहीं दी जानी चाहिए। यह उपक्रम का हिस्सा होगा। हम उन सभी कौशलों पर विचार करेंगे, जिनकी इस खंड में जरूरत होती है।' जब उनसे गैर-लाभकारी मॉडल के बारे में पूछा गया तो दासरी ने कहा कि जो लोग इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, उनका खर्च एक न्यास उठाएगा। दासरी का मानना है कि वह अपने बेटे संजय दासरी के कृषि कारोबार उद्यम वेकूल फूड्स की सफलता को समाज को कुछ लौटाने के अपने फैसले के पीछे की एक वजह मानते हैं। चेन्नई की वेकूल फूड्स तेजी से बढ़ रही कृषि-वाणिज्य कंपनियों में से एक है, जो खाद्य विकास एवं वितरण पर केंद्रित है। कंपनी का राजस्व चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये पर पहुंचने के आसार हैं। जब दासरी से कॉरपोरेट दुनिया छोड़ने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी दार्शनिक की तरह जवाब दिया।

उन्होंने कहा, 'मेरा जुनून या उपहार निवेशक उद्यम खड़े करना है। जीवन का अर्थ आपका उपहार ढूंढना है और जीवन का उद्देश्य इसे लौटाना है। मैं इसे कैसे लौटा सकता हूं। मैं इसे किसी एनजीओ को नहीं दे सकता। इसका बेहतर तरीका यह है कि ऐसा कुछ शुरू किया जाए, जो बढ़ता रहे ताकि रोजगार सहित समाज को कुछ लौटाया जा सके।' रॉयल एनफील्ड में दासरी की जगह सीईओ बी गोविंदराजन लेंगे, जो कंपनी में मुख्य परिचालन अधिकारी हैं।